

पहले मुख्य समाचार।

- लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर का किया समर्थन। कहा-निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार देना है संविधान।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े समारोह में समाज और राष्ट्र के चहुंमुखी विकास के लिए शिक्षा पर दिया जोर। नशा माफियाओं के प्रति अकादमिक संस्थाओं को सतर्क रहने की दी सलाह।
- यूनेस्को ने दीपावली को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित देश के कई गणमान्य लोगों ने जताई प्रसन्नता।
- उन्नीस दिसम्बर से शुरू होगा राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र

\*\*\*\*\*

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर का समर्थन करते हुए इस बात पर जोर दिया कि संविधान, निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार देना है। उन्होंने कहा कि एसआईआर, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध करना है।

फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान में जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी, अनुच्छेद 324 इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है।

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान, श्री शाह ने एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष, इस मुद्दे पर झूठ फैला रहा है और देश, सरकार तथा निर्वाचन आयोग की छवि धूमिल कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि निर्वाचन आयोग सरकार के अधीन काम नहीं करता है।

\*\*\*\*\*

एस आई आर पर एक तरफा झूठ फलाया है और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एस आई आर की प्रक्रिया का इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एस आई आर हुए, वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, उस झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूँ।

इस बीच, राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर का कार्य तेजी से जारी है। उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाटक ने कल मैनपुरी में एसआईआर को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी बूथों पर जाकर बीएलओ की मदद कर रहे हैं। श्री पाटक ने कहा कि एसआईआर लोकतंत्र की शुचिता के लिए जरूरी है।

\*\*\*\*\*

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तिरानवेवें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित मुख्य महोत्सव की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने अपने सम्बोधन में समाज और राष्ट्र के चहुंमुखी विकास के लिए शिक्षा को जरूरी बताया। मुख्यमंत्री ने नशा माफियाओं के प्रति अकादमिक संस्थाओं को सतर्क रहने की सलाह दी।

तेजी के साथ नशा माफिया युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। अकादमिक संस्थाओं को उसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। युवाओं को उसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है, उसको हम अवसर न दें।

इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। इस युवा पीढ़ी के दम पर वर्ष दो हजार सैंतालीस तक भारत को अर्थव्यवस्था और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में पहले स्थान पर आने से, विश्वगुरु बनने में मदद मिलेगी।

\*\*\*\*\*

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर रेलवे स्टेशन और झूले लाल रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों को गर्म कंबल और भोजन वितरित करने के साथ ही वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी हासिल की। एक रिपोर्ट-

रैन बसेरों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जरूरतमंद को शीतलहर से बचाने और सम्मानजनक आश्रय देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए जहां रैन बसेरों को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जा रहा है, वहीं

तहसीलों और नगर निकायों को जरूरतमंदों में ऊनी वस्त्र एवं कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ, प्लेटफार्म या सड़क पर खुले में न लेटे। यदि कोई ऐसा पाया जाता है उसे रैन बसेरों में पहुंचाया जाए और इसकी निरंतर निगरानी भी की जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह

\*\*\*\*\*

दीपोत्सव के पर्व दीपावली को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन-यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल यह घोषणा की।

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे, न कि समय के साथ लुप्त होती स्मृति। हमारे बच्चों को यह जानना चाहिए कि हम दीपक क्यों जलाते हैं, न कि केवल कैसे जलाते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि दीपावली रामराज्य का त्योहार है। यही सुशासन है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई गणमान्य लोगों ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्रीराम की पावन भूमि है। यहीं पर दीपावली की पहली ऐतिहासिक उत्सव परंपरा की शुरुआत हुई थी।

\*\*\*\*\*

राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र उन्नीस दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल ने 'बाई सर्कुलेशन' के जरिए इस सत्र की तिथियों को मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट—

उत्तर प्रदेश विधान मंडल का शीत कालीन सत्र 19 दिसम्बर से शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अनुमोदन के बाद सत्र की तिथियों की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। शीतकालीन सत्र 24 दिसम्बर तक जारी रहेगा। सत्र की संक्षिप्त अवधि के मद्देनजर राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकतायें साफ कर दी हैं। 22 दिसम्बर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये पहला अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा। इसमें कई विभागों की अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए धनराशि की मांग की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार सदन में 10 से अधिक विधेयक भी रखेगी, इनमें कुछ पुराने लंबित विधेयक और नये प्रस्ताव शामिल बताये जा रहे हैं। समाचार कक्ष से फजल इनाम।

\*\*\*\*\*

देश की पहली वेरिबल स्पीड पंप स्टोरेज परियोजना—टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की तीसरी यूनिट का वाणिज्यिक संचालन कल केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की वर्चुअल उपस्थिति में शुरू हुआ। ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि इस इकाई के उत्पादन से पचीस प्रतिशत बिजली उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगी, जिससे राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी।

\*\*\*\*\*

प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को अब विद्यालय शुरू होने के एक घंटे के अंदर ऑनलाइन हाजिरी लगानी अनिवार्य होगी। एक रिपोर्ट—

इस संबंध में शासन ने ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये हैं। शासन ने यह दिशा—निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर जारी किये हैं। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर स्कूल के प्रधानाध्यापक की होगी। हालांकि नेटवर्क समस्या होने पर ऑफलाइन हाजिरी का विकल्प भी मिलेगा और बगैर शिक्षकों का पक्ष सुने कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी। इस नई ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था का असर राज्य के लगभग एक लाख 33 हजार परिषदीय विद्यालयों और करीब साढ़े चार लाख शिक्षकों पर पड़ेगा। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

\*\*\*\*\*

काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में कल तमिलनाडु से पांचवां दल वाराणसी पहुंचा। दल में कलाकार और व्यवसायी शामिल हैं, जिन्हें मंदिर प्रशासन द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के भव्य कॉरीडोर का भ्रमण करवाया गया।

\*\*\*\*\*

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हो गया है। इसी माह पचीस दिसंबर को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे।

\*\*\*\*\*